गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 202
दि. 23.11.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

जी 20 में अमेरिका को दिखाई 'औकात'! साउथ अफ्रीका से मिला ऐसा संदेश कि गुस्से से लाल हो जाएंगे

(जीएनएस)।

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक घोषणापत्र पारित किया गया है, जिसने अमेरिकी विरोध के बावजूद सर्वसम्मति प्राप्त की। यह कदम G20 की परंपरा से हटकर माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के नेताओं ने अमेरिका की अनुपस्थिति में यह संयुक्त घोषणापत्र स्वीकार किया।

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक मतभेदों के कारण शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रिटोरिया पर घोषणापत्र स्वीकार न करने का दबाव भी डाला था। यह घटना वाशिंगटन और प्रिटोरिया के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है, लेकिन G20 ने जलवायु कार्रवाई पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

अमेरिका के विरोध के बावजूद जलवायु पर सहमति

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक घोषणापत्र पारित किया गया है, जिसने अमेरिकी विरोध के बावजूद सर्वसम्मति प्राप्त की। यह कदम G20 की परंपरा से हटकर माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के नेताओं ने अमेरिका की अनुपस्थिति में यह संयुक्त घोषणापत्र स्वीकार किया। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक मतभेदों के कारण शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रिटोरिया पर घोषणापत्र स्वीकार न करने का दबाव भी डाला था। यह घटना वाशिंगटन और प्रिटोरिया के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है, लेकिन G20 ने जलवायु कार्रवाई पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

अमेरिकी बहिष्कार के बाद भी बड़ा फैसला

G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका का बहिष्कार एक बड़ी राजनयिक घटना रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि इस बहिष्कार का मुख्य कारण मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका के राजनयिक मतभेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने पुष्टि की कि अमेरिका ने संयुक्त घोषणापत्र के शब्दों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन पर पारित घोषणापत्र पर फिर से बातचीत नहीं की जा सकती।

बीच तनाव स्पष्ट रूप से उजागर हुआ।

शिखर सम्मेलन की शुरूआत में घोषणापत्र

यह असामान्य रहा कि संयुक्त घोषणापत्र को शिखर सम्मेलन की कार्यवाही के शुरूआती दौर में ही स्वीकार कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इसे "व्यापक सहमति" का परिणाम बताया। उनके प्रवक्ता विंसेंट मैग्वेन्या ने कहा कि आमतौर पर घोषणापत्र को कार्यवाही के अंत में स्वीकार किया जाता है, लेकिन जबरदस्त समर्थन और तात्कालिकता को देखते हुए यह कदम उठाया गया। इस त्वरित स्वीकृति ने अमेरिका के दबाव के बावजूद G20 देशों की जलवायु परिवर्तन पर एकजुटता और प्रतिबद्धता को दर्शाया। यह G20 के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है।

ट्रंप ने घोषणापत्र को स्वीकार न करने का बनाया था दवाब

दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रिटोरिया पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वे उनकी गैर-मौजूदगी में G20 नेताओं के घोषणापत्र को स्वीकार न करें। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। प्रवक्ता विंसेंट मैग्वेन्या ने जोर देकर कहा कि "हमने इस घोषणापत्र को स्वीकार करने के लिए पूरे साल काम किया है और पिछला सप्ताह भी काफी जोरदार रहा है।" यह दशार्ता है कि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी संप्रभुता और G20 की सामूहिक भावना को प्राथमिकता दी, भले ही इसका मतलब अमेरिका के साथ राजनयिक तनाव को बढ़ाना हो।

G20 में शामिल हुए प्रमुख विश्व नेता

जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई प्रभावशाली देशों के नेता शामिल हुए। इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्योंग, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई अन्य महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। इन नेताओं की उपस्थिति ने जलवायु परिवर्तन पर घोषणापत्र को वैश्विक समर्थन प्रदान किया और G20 मंच की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शार्या, भले ही एक प्रमुख सदस्य अनुपस्थित रहा।

यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर, सीएम योगी का निर्देश- सख्त कार्रवाई करें

लखनऊ (जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध घुसपैठ को लेकर अफसरों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर का निर्माण किया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है

कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं।

इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता के अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा।

गोवा में आप की मजबूत तैयारी, जिला पंचायत चुनावों की सभी 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा

गोवा की राजनीति में आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। जिला पंचायत चुनावों के लिए पार्टी अब तक 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और सभी 50 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान सिर्फ नामों की लिस्ट भर नहीं है, बल्कि नई राजनीतिक दिशा का संकेत है जिसमें आप गोवा के गांवों, कस्बों और स्थानीय निकायों को सक्रिय और मजबूत बनाना चाहती है। यह कदम यह भी दिखाता है कि पार्टी ने गोवा में अपनी संगठनात्मक पकड़ को पिछले कुछ वर्षों में बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ताना-रीरी महोत्सव का भव्य शुभारंभ कराया

- मुख्यमंत्री का संगीत कला की स्वदेशी विरासत के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान
- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री कलापिनी कोमकली को ताना-रीरी संगीत सम्मान अवॉर्ड प्रदान किया

गांधीनगर,22 नवंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय संस्कृति के 2000 वर्षों के इतिहास को संजोए बैठे वडनगर में ताना-रीरी महोत्सव 2025 का शनिवार को शुभारंभ कराया। यह महोत्सव खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग अधीनस्थ गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी-गांधीनगर तथा मेहसाणा जिला प्रशासन के संयुक्त उपक्रम से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। शनिवार को महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री कलापिनी कोमकली को प्रतिष्ठित ताना-रीरी संगीत सम्मान अवॉर्ड प्रदान किया गया।

श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि वडनगर की भूमि में ही कुछ ऐसा सत्व-तत्व रहा है कि अनादिकाल से यहाँ समर्पण एवं सेवा साधना की पराकाष्ठा विकसित हुई है।

उन्होंने ताना-रीरी को अनमोल संगीत कला विरासत का उत्तम उदाहरण बताते हुए कहा कि उनकी तरह ही वडनगर के सपूत एवं विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी राष्ट्र प्रथम के भाव से कार्यरत रहकर देश तथा दुनिया के समक्ष सेवा साधना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कला एवं स्थापत्य की इस नगरी के इतिहास को पुनर्जीवित करने के सफल आयाम का सूत्रपात किया है।

श्री पटेल ने प्रधानमंत्री की विरासत संवर्धन नीतियों का विवरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जहाँ प्राथमिक शिक्षा ली, उसे प्रेरणा स्कूल के रूप में विकसित किया है। जहाँ उन्होंने बचपन में परिश्रम की पराकाष्ठा सृजित की, उस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है और मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इसके अलावा वडनगर की समग्र पुरातन विरासत को प्रस्तुत करने वाले अत्याधुनिक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का भी वडनगर में निर्माण हुआ है।

स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत वडनगर में हुए विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना अंतर्गत शर्मिष्ठा तालाब, ताना-रीरी पार्क, लटेरी वाव (बावड़ी), अंबाजी कोठा तालाब तथा फोर्ट वॉल का विकास किया जा रहा है, जबकि पौराणिक हाटकेश्वर मंदिर का इतिहास लोग जान सकें; इसके लिए लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय संगीत विरासत की समृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि आज रोग के उपचार के लिए भी म्यूजिक थेरेपी का उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी विरासत का युगों तक जतन एवं संवर्धन करने का संकल्प किया है।

वर्ष 2047 में विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को कला-संस्कृति के साथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि कला-संस्कृति की स्वदेशी विरासत का संरक्षण हो और आने वाली पीढ़ी को भी इस विरासत के जतन की प्रेरणा मिले।

मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया कि वडनगर की पवित्र धरती से इस कला-संस्कृति के जतन के साथ स्वदेशी अपना कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध हों।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इजराइल के साथ कृषि, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाया

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इजराइल की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान कई बैठकें कीं, जिससे कृषि, प्रौद्योगिकी, नवाचार और व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिला है।

श्री गोयल ने 21 नवंबर को अपनी बैठकों के दौरान, इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री श्री एवी डिचर से कृषि सहयोग को आगे बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। श्री डिचर ने श्री गोयल को इजराइल के 25 वर्षीय खाद्य सुरक्षा रोडमैप, उसकी उन्नत बीज-सुधार रणनीतियों और कृषि के लिए जल-पुनउपयोग प्रौद्योगिकियों में देश के वैश्विक नेतृत्व के बारे में जानकारी दी।

श्री गोयल ने अपनी यात्रा के दौरान पेरेज सेंटर फॉर पीस एंड इनोवेशन का दौरा किया, जहां उन्हें इजराइल के अग्रणी तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र से

अवगत कराया गया। उन्हें ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्टेंट तकनीक और आयरन डोम प्रणाली सहित कई ऐतिहासिक नवाचारों के साथ-साथ उभरती हुई भविष्य की तकनीकों और इमर्सिव वर्चुअल-रियलिटी समाधानों की जानकारी दी गयी। उन्होंने पेरेज सेंटर को एक प्रेरक संस्थान बताया जो इजराइल की रचनात्मकता, नवाचार और सामाजिक प्रभाव की प्रगति को दशार्ता है।

उन्होंने मोबाइलआई द्वारा आयोजित एक स्वचालित-ड्राइव प्रदर्शन के माध्यम से गतिशीलता समाधानों में इजराइल की प्रगति की भी जानकारी ली जिसमें अगली पीढ़ी की गतिशीलता में सटीक इंजीनियरिंग का उल्लेख किया गया।

श्री गोयल ने किबुत्ज रमत राचेल का भी दौरा किया जहां उन्होंने सहकारी जीवन शैली, टिकाऊ कृषि पद्धतियों और समुदाय-संचालित नवाचार के उनके मॉडल का अवलोकन किया। इन मुलाकातों से इजराइल की तकनीकी शक्तियों और ग्रामीण विकास एवं स्थिरता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।

इससे पहले 20 नवंबर को, श्री गोयल ने इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री श्री नीर बरकत के साथ बैठक की थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज की।

राज्य के किसानों से सोमवार 24 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान, बाजरे, ज्वार, मक्के, रागी की सीधी खरीद शुरू की जाएगी

- राज्य में निर्धारित केन्द्रों से 31 जनवरी, 2026 तक खरीद करने के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के एक और संवेदनशील निर्णय की कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने की घोषणा

गांधीनगर,22 नवंबर :राज्य सरकार सोमवार 24 नवंबर से खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 अंतर्गत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, बाजरे, ज्वार, मक्के तथा रागी की सीधी खरीद करेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपना कर बेमौसम बारिश से भारी नुकसान झेलने वाले किसानों को उबारने के लिए हाल ही में 10 हजार करोड़ रुपए का ऐतिहासिक राहत पैकेज दिया है।

अब श्री पटेल ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 अंतर्गत धान, बाजरे, ज्वार, मक्के तथा रागी की सीधी खरीद का किसान एवं गरीब कल्याणकारी निर्णय किया है।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने शनिवार को राजकोट में यह घोषणा करते हुए कहा कि धान के लिए प्रति हेक्टेयर 1500 किलोग्राम धान पंजीकृत किसानों से खरीदा जाएगा।

उन्होंने जोड़ा कि सोमवार 24 नवंबर से आगामी 31 जनवरी 2026 तक इस खरीद अंतर्गत धान के लिए राज्यभर में 113 खरीद केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा बाजरे के लिए 150, ज्वार के लिए 50, मक्के के लिए 82 तथा रागी के लिए 19 केन्द्र निर्धारित किए गए हैं, जहाँ से खरीद होगी।

उन्होंने आगे कहा कि इस खरीद अंतर्गत बाजरा प्रति हेक्टेयर 1848 किलोग्राम, ज्वार प्रति हेक्टेयर 1539 किलोग्राम, मक्का प्रति हेक्टयर 1864 किलो तथा रागी प्रति हेक्टेयर 903 किलोग्राम के अनुसार खरीदा जाएगा।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रति क्विंटल खरीद का जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, उसमें धान के लिए प्रति क्विंटल 2369 तथा 2389, बाजरे कि लिए 3075, ज्वार (हाइब्रिड) के लिए 3999, ज्वार (मालदंडी) के लिए 4049, मक्के के लिए 2400 और रागी के लिए 5186 रुपए मूल्य रहेगा।

समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर आ रही उपजों को खरीद कर राज्य के एनएफएसए तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत समाविष्ट किए गए 74 लाख परिवारों के 3.60 करोड़ लोगों को निःशुल्क वितरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है।

जे एण्ड के पुलिस ने एक और शख्स को किया अरेस्ट, पुलवामा के इलेक्ट्रीशियन को हिरासत में लिया

पुलवामा के रहने वाले इलेक्ट्रीशियन तुफैल नियाज भट्ट को "व्हाइट कॉलर" आतंकी मॉड्यूल मामले की चल रही जाँच के तहत गिरफ्तार किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुलिस की राज्य जाँच एजेंसी (SIA) ने शनिवार को दिल्ली के लाल कि ला

विस्फोट मामले से जुड़े "व्हाइट कॉलर" आतंकी मॉड्यूल में एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिसमें 10 लोग मारे गए थे।

पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तुफैल नियाज भट्ट के रूप में की है। लाल किले के पास हुए विस्फोट स्थल पर जली हुई गाड़ियों के पास पुलिसकर्मी खड़े हैं।

सम्पादकीय

वंशवाद आज भी मजबूत

देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह निर्मित हो गई है कि एक जमाने में वंशवाद के जो प्रबल विरोधी थे और जिन्हें गांधी परिवार पूटी आंख भी नहीं सुहाता था, वे इसके समर्थक व निष्ठावान अनुयायी हो गए हैं। इसी कारण राजनीतिक वंशवाद ने अब एक ब्रांड का रूप धारण कर लिया है।

राजनीतिक वुलों में संग्राम बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में वर्चस्व का संग्राम छिड़ गया है।

लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज खान को चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। परिवार के सदस्यों में मानसिक विवृति किस हद तक होती है, इसका उदाहरण देते हुए रोहिणी ने कहा है कि 'मुझे गालियां देते हुए कहा गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। इसके बदले में मैंने करोड़ों रुपए और चुनावी टिकट लिए। मुझे अब अपनी उदारता पर पछतावा हो रहा है। मेरा देश की सभी बेटियों से अनुरोध है कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने पिता को नहीं बचाएं।' लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव भी रोहिणी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं।

उन्होंने यहां तक कह दिया है कि 'यदि बहन रोहिणी का माता-पिता ने किसी भी भी तरह का मानसिक उत्पीड़न दिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए।' तेजप्रताप ने यहां तक कह दिया कि जयचंदों को जमीन पर दफन कर देंगे। राज और राजनीतिक वंशों में देखने में आया है कि जब तक वे प्रगति कर रहे होते हैं, तब तक उनमें एकता बनी रहती है, लेकिन पतन के समय ये वुनबे बिर जाते हैं। वुदरत का यह ऐसा जाल है कि वह वंशों के डीएनए में ही अलगाव के बीच बो देता है।

भारतीय लोकतंत्र की जमीन पर जड़ें जमाते राजनीति के वंश-वृक्ष देश की संवैधानिक संप्रभुता की जड़ां में मट्ठा घोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस समेत हरेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल में राजनीतिक उत्तराधिकार और वंशवाद को राजनीति के फलक पर स्थापित करने की होड़ लगी है। भाजपा में भी वंशवाद का रोग पनपा हुआ है।

वामदलों को जरूर हम अपवाद के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे दलों की मानसिकता पर वुठाराघात करते हुए उन्हें लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना का विरोधी बताते हुए हमेशा हमलावर रहे हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति को सामंतशाही की संरक्षक और लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं के लिए घातक बताया है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि विवृत वंशवादी मनोवृत्ति के चलते बहुदलीय शासन प्रणाली, एकतंत्रीय व्यक्तिवाद की गिरफ्त में आती जा रही है।

इस नाते देश के प्रमुख राष्ट्रीय दल संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को एकध्रुवीय बनाने की कोशिश में लगे रहे हैं। कांग्रेस ने तो समूची राजनीति को राहुल गांधी और क्षेत्रीय दलों ने परिवार के मुखियाओं पर वेंद्रित कर दी है।

जबकि संवैधानिक व्यवस्था बहुदलीय है। लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का यह खेल न तो देश की बुनियादी समस्याएं भूख, अन्याय और असमानता से लड़ने में कामयाब हो सकती हैं और न ही सीमाईं संप्रभुता व आंतरिक समस्याओं से निपटने में दो-चार हो सकती हैं? दरअसल आसानी से मिला राजनैतिक उत्तराधिकार का वैभव व्यक्ति की मानसिकता को सुविधा-भोगी और व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का काम करता हैं। वह राजसी भोग-विलास में भी लग जाता है। प्रजातंत्र में यह स्थिति अपरोक्ष रूप से सामंती मूल्यों को स्थापित करने वाली है।

बुंदेलखण्ड में एक कहावत प्रचलित है कि चंबल नदी की गहराईं एक दर्जन खाटों की बान से भी नहीं नापी जा सकती? लेकिन प्रजातंत्र की मिट्टी में वंशवाद की जड़ें जितनी गहरी होती जा रही हैं,उन्हें तो दो दर्जन खाटों के बान से भी नहीं नापा जाना मुश्किल है?

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का नई नियुक्ति पाने वाले 4400 से अधिक युवाओं का आ'ान

गांधीनगर,22 नवंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों में वर्ग-3 में नई नियुक्ति प्राप्त कर रहे 4,473 युवाओं का आ'ान किया है कि वे राज्य सरकार की सेवा में उन्हें मिले अवसर को केवल नई नियुक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आम आदमी की सेवा से राष्ट्र निर्माण में योगदान के अवसर के रूप में स्वीकारें।

इस संदर्भ में श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार में 'नागरिक देवो भवः' का मंत्र अपनाया है और लोगों को गुड गवर्नेंस की निरंतर प्रतीति कराई है। उन्होंने कहा कि नई नियुक्ति पा रहे युवाओं से अपेक्षा है कि वे भी प्रामाणिकता के साथ कार्यरत रहकर, किसी छोटे आदमी की मुश्किल दूरकर या किसी विधवा माता के आँसू पोंछकर तथा निराधार का आधार बनकर अपने वाणी-बर्ताव एवं व्यवहार से लोगों को संवेदनशील सरकार की अनुभूति कराएँ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की विशेष उपस्थिति में शनिवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 'विकसित भारत, विकसित गुजरात' अंतर्गत गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल (गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानी जीएसएसएसबी) द्वारा सरकार के विभागों में विभिन्न कैडर में चयनित कुल 4,473 उम्मीदवारों में से लगभग 21 उम्मीदवारों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहा कि वे ड्यूटी और कार्य में शिथिलता नहीं, बल्कि नवीनता के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रहित प्रथम एवं राज्य के विकास से राष्ट्र के विकास के भाव को समग्र कॅरियर में प्राथमिकता देकर 2047 के विकसित भारत के निर्माण के संवाहक बनें।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपरेंसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग और 'मन रिसोर्स मैनेजमेंट पर जो फोकस किया है, उसे गुजरात ने पारदर्शी नियुक्ति से साकार किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग से कार्यरत किए गए 3000 से अधिक कैडर की जानकारी से युक्त कैडर मैनेजमेंट पोर्टल तथा 10 वर्षीय भर्ती कैलेंडर का विवरण दिया। इसके परिणामस्वरूप मैन पावर रिक्रूटमेंट का आयोजन सरल बना है। रोजगार वांछु युवाओं को भी परीक्षा की अग्रिम जानकारी मिलती है और वे पूर्ण तैयारी कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुए रोजगार मेलों से देश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अतिरिक्त निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में 'हर हाथ को काम, हर काम का सम्मान' का ध्येय साकार करने वाले रोजगार के अवसर खुले हैं तथा 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री के विजन से 'पीएम विकसित भारत योजना' शुरू हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नई नियुक्ति पा रहे युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का गुजरात सरकार परिवार में स्वागत-सह-अभिनंदन करते हुए कहा कि आज का दिन गुजरात की युवा शक्ति के लिए एक स्वर्णिम दिवस है। आज जब सभी उम्मीदवारों ने अथक परिश्रम के अंत में यह उपलब्धि प्राप्त की है, तब उनके माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों के सपने भी साकार हुए होंगे। यह सफलता जनसेवा की नई शुरूआत है। नई नियुक्ति पाने वाले सभी उम्मीदवारों को राज्य के नागरिकों के काम करने के लिए अवसर मिला है। उन्होंने इस अवसर का उपयोग नागरिकों की सेवा करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हो; इसका ध्यान रखने का अनुरोध किया।

श्री संघवी ने कहा कि अप्रैल-2025 से अब तक गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल द्वारा लगभग 101 परीक्षाएँ आयोजित कर रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने ऑनलाइन, पारदर्शी एवं त्वरित भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने वाले गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल की समग्र टीम को अभिनंदन दिया।

उन्होंने इस अवसर पर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियाँ करने वाले राज्य के लाखों युवाओं के लिए इसी महीने के अंत तक गुजरात पुलिस बल में 14,507 नई रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया घोषित की जाएगी।

ऑपरेशन दृष्टिः जम्मू-कश्मीर के उत्तरी कमान स्थित कमांड अस्पताल में अपनी तरह के पहले उन्नत सर्जिकल नेत्र शिविर मे2,000से ज्यादा लोगों की जांच की गई और 400 सर्जरी की गईं

(जीएनएस)।

एक अद्वितीय उन्नत शल्यचिकित्सा नेत्र शिविर 'ऑपरेशन दृष्टि'का आयोजन' 18-22नवंबर, 2025को कमांड अस्पताल, उत्तरी कमांड, उधमपुर में किया गया, जिसमें नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल) की शल्यचिकित्सा टीम ने अपनी सहभागिता की। शिविर में लोगों की भागीदारी उम्मीद से बढ़कर रही क्योंकि 2,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई और 400 से ज्यादा सर्जरी की गईं, जिनमें मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और रेटिना संबंधी बीमारियों की जटिल प्रक्रियाएंशामिल है। शिविर उम्मीद से बढ़कर रहा क्योंकि 2,000 से ज्यादा लोगों की जाँच की गई और 400 से ज्यादा सर्जरी की गईं, जिनमें मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और रेटिना संबंधी बीमारियों की जटिल प्रक्रियाएं शामिल थीं। सेवारत कर्मियों, आश्रितों, वीर नारियों (युद्ध विधवाओं) और स्थानीय नागरिकों सहित लोग जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज के इलाकों से आए थे, जिनमें उधमपुर, डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, रामबन आदि के दूरदराज के गांव शामिल थे।

सर्जिकल टीम में कुशल एवं अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञ शामिल थे, जिनका नेतृत्व ब्रिगेडियर एसके मिश्रा ने किया, जो एक विशिष्ट नेत्र शल्य चिकित्सक और आर्मी हॉस्पिटल में नेत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं, जिन्हं भारतीय राष्ट्रपतियों का ऑपरेशन किया है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 20 नवंबर, 2025 को इस शिविर का दौरा किया और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने नेत्र विज्ञान विभाग का दौरा किया, जहां उन्हें अस्पताल की अत्याधुनिक सुविधाओं, रोगी देखभाल कार्यक्रमों और चल रही निःशुल्क आंख-सक्रिनिंग पहलों के बारे में जानकारी ली। डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय सेना की बहुआयामी भूमिका की सराहना की और कहा कि युद्ध के समय सेना की सेवा असाधारण है, शांति के समय मानवता के प्रति उसका योगदान एव समाज की सेवा में समर्पण भी बहुत महान है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल केवल राष्ट्र की सुरक्षा ही नहीं करते बल्कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और मानवीय सेवाएँ भी प्रदान करते हैं, जो नागरिकों के कल्याण के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

लाभार्थियों में पुंछ के 72 वर्षीय वयोवृद्ध श्री सुरिंदर सिंह भी शामिल हैं। वे न केवल दो-तीन वर्षों से अंधेपन से जूझ रहे थे, बल्कि वे के गहरे, अमिट घाव भी ढो रहे थे। उन्होंने अपने पड़ोस में उस त्रासदी को देखा था जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलाबारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप उनके पड़ोसियों जो उनके परिवारों के मुख्य कमाने वाले और आधार स्तंभ थे की जान चली गई थी। श्री सुरिंदर सिंह ने अपनी कृतज्ञता को क्रियाशीलता के कारण अपनी वापस पाई हुई दृष्टि और दुःख की समझ का उपयोगं करके व्यक्तिगत रूप से उन साथी नागरिकों को सक्रिय किया जो दुःख और कठिनाइयों से परेशान थे।

इसी प्रकार, मेंढर के 56 वर्षीय सेवानिवृत्त सैनिक अब्दुल्ला शफीक ने हाल के संघर्ष से प्रभावित निवासियों के लिए इन विशेष नेत्र चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस शिविर से जीवन-परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त हुआ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजकुमारी देवी हैं, जो 96 वर्ष की हैं। उन्होंने स्पष्ट दृष्टि का उपहार प्राप्त हुआ और अब पूरी स्पष्टता के साथ दुनिया देखने की अनमोल क्षमता रखती हैं।

इस प्रभावशाली चिकित्सा मिशन की उत्पत्ति सेवा की साझा दृष्टि में निहित हैजिसे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया था जो कि उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के अनुरोध के बाद हुआ था। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहल की तत्काल आवश्यकता की बात करते हुए, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना चिकित्सा के उच्चतम स्तरोंडी, जी, एएफएमएस और डीजी मेडिकल सर्विसेज (आर्मी), को कैंप के संचालन की सावधानीपूर्वक योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने का निर्देश दिया। उन्होंने नैदानिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए, सेना प्रमुख ने उधमपुर के परिचालनीय क्षेत्र में एक विशेष कैंप स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

संयुक्त आर्थिक क्षेत्र- ईईजेड की निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना का युद्धपोत 'सावित्री' सेशेल्स के दौरे पर

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) आईएनएस सावित्री हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के तहत सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा हुआ है। इसके आगमन पर सेशेल्स तटरक्षक बल के कर्मियों ने पोत का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह पहल दोनों देशों के बीच गहरे पारस्परिक सम्मान, मजबूत रक्षा सहयोग और सुदृढ़ होते द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को दशार्ती है।

पोर्ट कॉल के दौरान जहाज ने सेशेल्स तटरक्षक बल को महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स सौंपे, जिससे साझा समुद्री क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपने साझेदार देशों की परिचालन क्षमता एवं तत्परता बढ़ाने के प्रति भारत की अटूट वचनबद्धता एक बार फिर स्पष्ट हुई।

आईएनएस सावित्री ने अपने बंदरगाह प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिनमें कार्यात्मक बातचीत, विषय-वस्तु विशेषज्ञों के साथ तकनीकी आदान-प्रदान और सेशेल्स तटरक्षक बल के साथ सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना शामिल था। इसके अलावा, जहाज को आगंतुकों के लिए भी खोला गया, जहां उन्हें भारतीय नौसेना की उन्नत परिचालन क्षमताओं और समृद्ध समुद्री परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिला।

आईएनएस सावित्री सेशेल्स तटरक्षक बल के साथ मिलकर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की संयुक्त निगरानी करेगा। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य सेशेल्स के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा, सतर्कता एवं स्थितिजन्य जागरूकता को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। हिंद महासागर क्षेत्र में आईएनएस सावित्री की यह तैनाती भारत के 'क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति' (महासागर) के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत को एक विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार व प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में स्थापित करती है।

क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे दिन स्थायी वित्तपोषण, क्षेत्रीय सहयोग और एआई-सक्षम शासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया

(जीएनएस)।

क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (आरओडीएचएस) 2025 ने नई दिल्ली में प्रगतिशील चचाओं के अपने तीसरे और अंतिम दिन का समापन किया, जिसमें सरकारी विभागों के प्रमुखों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया, ताकि दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में डिजिटल स्वास्थ्य और एआई सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके।

दिन के सत्र चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर केंद्रित रहेः व्यक्ति-केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियाँ, स्थायी वित्तपोषण मॉडल, डिजिटल और एआई-सक्षम स्वास्थ्य के लिए शासन ढाँचा, और क्षेत्रीय सहयोग तंत्र। सत्रों में इस बात पर जोर दिया गया कि केवल तकनीक ही स्वास्थ्य सेवा में बदलाव नहीं ला सकती, जब तक कि उसके साथ मजबूत शासन, अंतर-संचालन और समावेशी कार्यान्वयन रणनीतियाँ न हों।

यूनिसेफ ने व्यक्ति-केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों पर एक सत्र की सुविधा प्रदान की, जिसमें भारत, श्रीलंका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के डिजिटल स्वास्थ्य विशेषज्ञ को एक साथ लाया गया ताकि व्यक्ति-केंद्रित, अंतर-संचालनीय और बुद्धिमान डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के साझा दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जा सके जो पहुंच, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करते हैं।

उत्तर प्रदेश एक दिलचस्प केस स्टडी के रूप में उभरा, जिसमें वक्ताओं ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ एकीकरण, स्कैन एंड शेयर को अपनाने और डिजिटल नागरिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला।

श्रीलंका में डिजिटल स्वास्थ्य विकास ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया है - सिर्फ डेटा एकत्र करने से आगे बढ़कर अब ऐसे व्यावहारिक, परिणाम-उन्मुख सिस्टम लागू किए जा रहे हैं जो वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित करते हैं। यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने पूरे क्षेत्र में देखभाल और साक्ष्य-आधारित योजना की निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सामंजस्यपूर्ण ढाँचों के ज़िम्मेदाराना उपयोग के महत्व पर जोर दिया।

डिजिटल स्वास्थ्य रूपांतरण के लिए सतत वित्तपोषण मॉडल भी एक महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकता के रूप में उभरा है, विशेषकर ऐसे समय में जब वित्तीय संसाधन सीमित हो रहे हैं, स्वास्थ्य-क्षेत्र की लागत बढ़ रही है और वैश्विक सहायता में लगातार कमी आ रही है। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते ने साझा चुनौतियों की पहचान की, जिनमें बिखरे हुए वित्तपोषण स्रोत, दाता-निर्भरता और दीर्घकालिक बजट की कमी शामिल हैं - ये सभी डिजिटल हेल्थ प्रगति को कमजोर करने का खतरा पैदा करते हैं।

एक प्रमुख विषय कानूनी और नियामक सुधारों की तत्काल आवश्यकता थी, जिसमें डेटा सुरक्षा कानून, डिजिटल स्वास्थ्य अधिनियम, खरीद आधुनिकीकरण और दीर्घकालिक डिजिटल स्वास्थ्य निवेशों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर शासन व्यवस्था शामिल थी। पैनलिस्टों ने सार्वजनिक निधियों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, संयुक्त बजट और बीमा-संबंधी निवेशों सहित मिश्रित वित्तपोषण दृष्टिकोणों पर भी जोर दिया।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव और इंडियाएआई मिशन के सीईओ, श्री अभिषेक सिंह ने डिजिटल एवं एआई-सक्षम स्वास्थ्य प्रणाली के लिए शासन की पुनर्कल्पना पर एक मुख्य प्रस्तुति दी।

रक्षा सचिव ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एनसीसी के 78वें स्थापना दिवस समारोह की अगुवाई की

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) 23 नवंबर, 2025 को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह की शुरूआत में, 22 नवंबर, 2025 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली में एक भव्य पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया, जहां रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम ने राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरूआत कर दी, जिसमें राष्ट्र निर्माण और युवा विकास में एनसीसी की अटूट भूमिका को रेखांकित किया गया।

तीनों सेनाओं की तीन एनसीसी बालिका कैडेटों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की, और देश के वीरों के सम्मान में वरिष्ठ नेतृत्व के साथ शामिल हुईं। समारोह के बाद, रक्षा सचिव, एनसीसी महानिदेशक और उपस्थित लोगों ने दिल्ली के विभिन्न स्कूलों से आए एनसीसी कैडेटों की बैंड प्रस्तुति देखी, जिसने इस स्मृति समारोह को और भी भव्य बना दिया।

1948 में मात्र 20,000 कैडेटों के साथ अपनी स्थापना से लेकर, आज एनसीसी 20 लाख कैडेटों के साथ विश्व का सबसे बड़ा वदीर्धारी युवा संगठन बन गया है। इसमें 2014 और 2025 के बीच 6 लाख कैडेटों की वृद्धि शामिल है। आज, इसकी उपस्थिति देश के 780 जिलों में से 713 तक फैली हुई है, जिससे यह देश में सबसे व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व वाले युवा संस्थानों में से एक बन गया है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, कैडेटों ने रक्तदान अभियान, वृक्षारोपण गतिविधियां, 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान और नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा-विरोधी जागरूकता कार्यक्रमों जैसी कई जन-सेवा पहलों के माध्यम से इस दिवस को मनाया। इन प्रयासों ने सामुदायिक सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व पर एनसीसी के निरंतर ध्यान को प्रदर्शित किया।

रक्षा सचिव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में एनसीसी के योगदान की सराहना की। उन्होंने आपदा मित्र आपदा-प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, एनसीसी माउंट एवरेस्ट अभियान और पाठ्यक्रम में ड्रोन एवं साइबर प्रशिक्षण को शामिल करने जैसी प्रमुख पहलों पर जोर दिया।

एनसीसी अपनी 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। एनसीसी एक जीवंत और भविष्य के लिए तैयार संगठन के रूप में विकसित हो रहा है, जो विकसित भारत को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध अनुशासित, सामाजिक रूप से जागरूक और तकनीकी रूप से कुशल युवाओं को तैयार कर रहा है।

शिक्षा मंत्रालय 2 दिसंबर, 2025 से काशी तमिल संगमम (केटीएस) 4.0 का आयोजन करेगा

(जीएनएस)।

शिक्षा मंत्रालय 2 दिसंबर, 2025 से तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों का उत्सव मनाने के लिए काशी तमिल संगमम (केटीएस) 4.0 के चौथे संस्करण का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित यह पहल, दोनों क्षेत्रों के बीच सभ्यतागत, सांस्कृतिक, भाषाई और लोगों के बीच संबंधों का सम्मान करती है और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दशार्ता है।

इस कार्यक्रम का आयोजन आईआईटी मद्रास और बीएचयू वाराणसी के समन्वय से किया जा रहा है, तथा संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है।

2022 में अपनी स्थापना के बाद से, काशी तमिल संगमम में भारी जनभागीदारी देखी गई है और यह भारत की दो प्राचीन ज्ञान परंपराओं को पुनः जोड़ने वाले एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सेतु के रूप में उभरा है। केटीएस के पिछले तीन संस्करणों की सफलता के आधार पर, चौथे संस्करण का उद्देश्य सीखने के आदान-प्रदान, सांस्कृतिक विसर्जन, अकादमिक बातचीत और अधिक से अधिक युवा भागीदारी के माध्यम से जुड़ाव को और बढ़ाना है।

2025 का विषयः 'तमिल सीखें - तमिल करकलम'

केटीएस 4.0 का आयोजन "तमिल सीखें - तमिल करकलम" विषय पर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में तमिल सीखने को बढ़ावा देना और भारत की शास्त्रीय भाषाई और साहित्यिक विरासत के लिए व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना है।

केटीएस के इस संस्करण में तमिलनाडु से 1,400 से अधिक प्रतिनिधि निम्नलिखित सात श्रेणियों में भाग लेंगेः

1. छात्र, 2. शिक्षक, 3. लेखक और मीडिया पेशेवर, 4. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, 5. पेशेवर और कारीगर, 6. महिलाएं, 7. आध्यात्मिक विद्वान और अभ्यासी

प्रतिनिधि 8 दिवसीय अनुभवात्मक दौरे पर जाएंगे, जिसमें वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्राएं, बातचीत, सेमिनार, सांस्कृतिक प्रदर्शन और स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प और विरासत से परिचय शामिल होगा।

प्रतिनिधियों को वाराणसी के महत्वपूर्ण तमिल धरोहर स्थलों, जिनमें महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार का पैतृक निवास, केदार घाट, "लघु तमिलनाडु" क्षेत्र में स्थित काशी मदम, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और माता अन्नपूर्णा मंदिर स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। वे अकादमिक और साहित्यिक बातचीत के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के तमिल विभाग का भी दौरा करेंगे।

केटीएस 4.0 के अंतर्गत प्रमुख पहल

1. तेनकासी से काशी तक ऋषि अगस्त्य का वाहन अभियान

तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सांस्कृतिक मार्गों का पता लगाने वाला " ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान " भी 2 दिसंबर 2025 को तेनकाशी से शुरू और 10 दिसंबर 2025 को काशी में समाप्त होने की योजना है। यह अभियान पांडियन शासक श्री आदि वीर पराक्रम पांडियन के प्रयासों का प्रतीक है, जिन्होंने तमिलनाडु से काशी तक की अपनी यात्रा के माध्यम से भारतीय संस्कृति में एकता का संदेश फैलाया और एकता की भावना को रेखांकित करने के लिए शहर का नाम बदलकर तेनकाशी (दक्षिण काशी) रखते हुए भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

पश्चिम रेलवे की फर्जी टिकटों पर सख्त कार्रवाई, अक्टूबर व नवंबर 2025 में कई मामलों का पता लगाया

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षित, पारदर्शी व निष्पक्ष यात्रा सुनिश्चित करने के लिए फर्जी टिकटिंग के विरुद्ध अपनी सतर्कता को और मजबूत किया है। अक्टूबर-नवंबर 2025 के दौरान पश्चिम रेलवे के सतर्क टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा नकली मोबाइल टिकट, नकली आरक्षित टिकट तथा रियायतों के दुरुपयोग से जुड़े चार महत्वपूर्ण मामले पकड़े गए।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की गई तथा संबंधित यात्रियों को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु जीआरपी के सुपुर्द किया गया।

पहले मामले में टिकट चेकिंग स्टाफ प्रदीप कुमार ने ए.सी. उपनगरीय लोकल में एक डिजिटल रूप से संपादित मोबाइल टिकट पकड़ा, जिसमें ₹15/- के टिकट को डिजिटल एडिटिंग टूल्स का उपयोग कर फर्जी तरीके से सीजन टिकट में बदल दिया गया था। नियमित चेकिंग के दौरान यह हेरफेर सामने आया, जिसके बाद यात्री को हिरासत में लेकर जीआरपी के हवाले किया गया।

टिकट चेकिंग स्टाफ प्रदीप कुमार | टिकट चेकिंग स्टाफ मोहम्मद जाहिद कुरैशी | टिकट चेकिंग स्टाफ अब्दुल अजीज | टिकट चेकिंग स्टाफ साई प्रसाद

दूसरा मामला टिकट चेकिंग स्टाफ मोहम्मद जाहिद कुरैशी द्वारा एक लंबी दूरी की ट्रेन में पकड़ा गया। रियायत के लिए अपात्र दो यात्री विकलांग कोटा में बुक किए गए टिकटों पर यात्रा कर रहे थे। रियायत का लाभ लेने के लिए किराया विवरण में छेड़छाड़ की गई थी, जबकि यात्री इसके पात्र नहीं थे। दोनों यात्रियों को तुरंत जीआरपी को सौंप दिया गया।

तीसरा मामला टिकट चेकिंग स्टाफ मोहम्मद जाहिद कुरैशी और अब्दुल अजीज द्वारा संयुक्त रूप से एक मेल/एक्सप्रेस ट्रेन में पकड़ा गया। एक नकली तत्काल आरक्षित टिकट, जो एक अनधिकृत एजेंट से अधिक दर पर खरीदा गया था, जांच के दौरान पाया गया। यात्री ने इसे अवैध तरीके से प्राप्त करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसे जीआरपी के सुपुर्द किया गया।

चौथे मामले में टिकट चेकिंग स्टाफ साई प्रसाद ने ए.सी. उपनगरीय लोकल में डिजिटल रूप से संपादित मोबाइल टिकट पकड़ा। इसमें क्यूआर कोड और प्रमुख टिकट विवरणों से अनधिकृत ग्राफिक टूल्स का उपयोग कर छेड़छाड़ की गई थी। निरीक्षण में टिकट फर्जी पाए जाने के बाद संबंधित यात्री को हिरासत में लेकर जीआरपी कर्मियों को सौंप दिया गया।

पश्चिम रेलवे की यात्रियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत माध्यमों, जैसे यूटीएस ऐप, आईआरसीटीसी ऐप, पीआरएस/यूटीएस बुकिंग काउंटर आदि से ही टिकट खरीदें,

भारत 'पृथ्वी संरक्षण'पर वैश्विक अभियान का नेतृत्व करने में सक्षम: डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ में 26वें 'अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन' को संबोधित किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञानराज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत "पृथ्वी संरक्षण" पर वैश्विक अभियान का नेतृत्व करने में सक्षम है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, उभरती प्रौद्योगिकियों और पृथ्वी संरक्षण की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन का आ'ान किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने लखनऊ के सीएमएस कानपुर रोड स्थित वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर में 26वें 'अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन' में "जलवायु न्याय और पृथ्वी संरक्षण: मौजूदा चुनौतियों के लिए कानूनी रूपरेखा" विषय पर पैनल चर्चा को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज न्यायाधीश संवैधानिक व्याख्या, वैज्ञानिक समझ और नैतिक जिम्मेदारी

के चौराहे पर खड़े हैं, ऐसे में मानवता के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन, महामारियां, साइबर खतरे, महासागरीय क्षरण और तेजी से बदलती तकनीकी बाधाएं जैसे "अंतसंबंधित संकटों" के दौर से गुजर रही है। इनमें से कोई भी राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये वैश्विक खतरे समानता, अखंडता और अंतर-पीढ़ीगत न्याय पर आधारित वैश्विक कानूनी प्रतिक्रियाओं की मांग करते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पहले ही गहरा महासागर मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से लेकर साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और अंतरिक्ष सुधारों में महत्वाकांक्षी पहलों तककई भविष्योन्मुखी मिशनों में खुद को अग्रणी स्थान पर स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये पहल वैश्विक पर्यावरणीय प्रबंधन और प्रौद्योगिकी विनियमन में सार्थक योगदान देने के लिए भारत की तत्परता को दशार्ती हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह नेनिजता बनाम निगरानी, स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वामित्व बनाम डेटा संरक्षण, तथा एआई जनित गलत सूचनाओं की बाढ़ जैसी उभरती कानूनी चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से उन क्षेत्रों में कानूनों की व्याख्या करने की अपेक्षा की जाएगी, जो दो दशक पहले तक अकल्पनीय थे, जिनमें अंतरिक्ष मलबा और बा' अंतरिक्ष खनन, गहरे समुद्र में संसाधनों का दोहन, सीमा पार जलवायु जवाबदेही तथा साइबर सुरक्षा और एआई नैतिकता का उभरता परिदृश्य शामिल है।

भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 25-26 में 1 बिलियन टन माल ढुलाई का आंकड़ा पार किया

(जीएनएस)।

भारतीय रेलवे का माल ढुलाई प्रदर्शन भारत की आर्थिक ढांचे को मजबूत कर रहा है। इस वर्ष संचयी लोडिंग 1 बिलियन टन के आंकड़े को पार कर गई है - 19 नवंबर तक 1020 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गई है।

यह उपलब्धि प्रमुख क्षेत्रों से व्यापक समर्थन को दशार्ती है: कोयला 505 मिलियन टन के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, इसके बाद लौह अयस्क (115 मिलियन टन), सीमेंट (92 मिलियन टन), कंटेनर ॅ यापार (59 मिलियन टन), कच्चा लोहा और तैयार इस्पात (47 मिलियन टन), उर्वरक (42 मिलियन टन), खनिज तेल (32 मिलियन टन), खाद्यान्न (30 मिलियन टन), इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल (लगभग 20 मिलियन टन), और शेष अन्य वस्तुएँ (74 मिलियन टन) हैं। दैनिक लोडिंग लगभग 4.4 मिलियन टन पर मजबूत बनी हुई है, जो पिछले वर्ष के 4.2 मिलियन टन से ज्यादा है, जो बेहतर परिचालन दक्षता और निरंतर माँग को दशार्ता है।

कोयला मालगाड़ी

अप्रैल से अक्टूबर के बीच माल लदान इस सकारात्मक प्रगति को और भी पुख्ता करता है, जो 2025 में 935.1 मिलियन टन तक पहुँच जाएगा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 906.9 मिलियन टन था, जो साल-दर-साल एक अच्छी वृद्धि दशार्ता है। यह निरंतर गति, बेहतर दैनिक लदान दरों के साथ, भारत के औद्योगिक विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग देने की रेलवे की क्षमता को दशार्ता है।

लोहे का लदान

भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में सीमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, रेलवे ने इस क्षेत्र की रसद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में लागू किए गए व्यापक सुधार, जिनमें बल्क सीमेंट टर्मिनलों के लिए नीति और कंटेनरों में बल्क सीमेंट की आवाजाही के लिए तर्कसंगत दरें शामिल हैं, सीमेंट परिवहन के आधुनिकीकरण की एक रणनीतिक पहल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन उपायों का उद्देश्य बल्क हैंडलिंग क्षमता बढ़ाना, पारगमन समय कम करना और रसद लागत कम करना है, जिससे उद्यमियों और अंतिम उपभोक्ताओं, दोनों को सीधा लाभ होगा और साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता बढ़ेगी। ऐसे लक्षित हस्तक्षेप क्षेत्रीय परिवर्तन को गति प्रदान करते हैं।

उर्वरक उतारना

थोक माल की आवाजाही को रेल द्वारा स्थानांतरित करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं जो केवल व्यावसायिक मानकों से कहीं आगे है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, राजमार्गों पर भीड़भाड़ कम होती है, और एमएसएमई सहित उद्योगों को हरित लॉजिस्टिक्स समाधानों तक पहुँच मिलती है। ये विकास सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हैं, माल ढुलाई को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों की ओर देश की यात्रा के साथ जोड़ते हैं और रेलवे को आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति, दोनों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करते हैं।

भारतीय हज समिति ने हज 2026 की तैयारियों को बढ़ाने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया

पूर्ण डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय पारदर्शिता और बेहतर हज यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना

(जीएनएस)।

भारतीय हज समिति (एचसीओआई) ने आज हज-2026 के लिए भारतीय हज यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने की।

सम्मेलन की शुरूआत 17 नवंबर को मदीना में हुई दुखद बस दुर्घटना में मारे गए हज यात्रियों की स्मृति में दो मिनट के मौन के साथ हुई।

अपने संबोधन में, सचिव डॉ. कुमार ने भारतीय हज समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हज से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह से डिजिटल, पोर्टल-आधारित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से एकीकृत हों, जिससे मैन्युअल प्रक्रियाओं की आवश्यकता समाप्त हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्नत तकनीक के युग में, कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण प्राथमिकता होनी चाहिए।

डॉ. कुमार ने आवेदन चरण से लेकर हज के बाद की सेवाओं तक

हज यात्रियों की सहायता के लिए मजबूत डिजिटल प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे सूचना, सहायता और वित्तीय लेनदेन तक बिना रुकावट के पहुंच सके।

इसके अलावा, डॉ. सी.एस. कुमार ने भारतीय हज समिति को निर्देश दिया कि वह हज यात्रियों के सभी लंबित बकाये का 75% तुरंत वापस कर दे, तथा शेष 25% का भुगतान सत्यापन, उचित परिश्रम और लेखा परीक्षा के बाद किया जाए। उन्होंने समिति को सलाह दी कि वह लेखा प्रक्रियाओं को संभालने के लिए एक पेशेवर वित्तीय प्रबंधन सेवा (एफएमएस) कंपनी को नियुक्त करे और तीर्थयात्रियों को 247 स्व-सहायता प्राप्त वित्तीय लेनदेन सहायता प्रदान करे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिले।

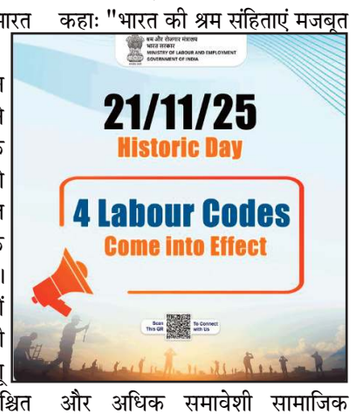

भारतीय हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शानवास सी ने मंत्रालय को आश्वासन दिया कि समिति हज यात्रा को पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सुचारू, अधिक कुशल और हज यात्रियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। संयुक्त सचिव राम सिंह, जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया था, ने हज यात्रा को आसान बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।

विभिन्न राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हज समितियों के प्रतिनिधियों ने जमीनी स्तर पर जानकारी साझा की तथा हाल के वर्षों में हज यात्रियों के समक्ष आने वाले कई मुद्दों को उठाया।

प्रमुख चिंताएं निम्नलिखित हैं:

-आरोहण स्थलों तक लंबी यात्रा दूरी

-बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम तीर्थयात्रियों के लिए पहुंच संबंधी चुनौतियाँ

भारतीय हज समिति ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय और संबंधित हितधारकों के परामर्श से इन मुद्दों का समाधान किया जाएगा, जिससे हज-2026 के लिए बेहतर सुविधाएं, उन्नत लॉजिस्टिक व्यवस्था और उन्नत सहायता प्रणालियां सुनिश्चित होंगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय हज समिति ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और तीर्थयात्री-केंद्रित हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

समावेशी आपदा जोखिम डेटा गवर्नेंस पर आपदा सूचना प्रबंधन के विकास के लिए एशियाई और प्रशांत केंद्र (एपीडीआईएम) का 10वां सत्र विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित

(जीएनएस)।

समावेशी आपदा जोखिम डेटा शासन पर एशियाई और प्रशांत आपदा सूचना प्रबंधन विकास केंद्र (एपीडीआईएम) का 10वां सत्र विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने किया। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह और एनडीएमए के सचिव श्री मनीष भारद्वाज भी शामिल थे।

उद्घाटन भाषण में, श्री नित्यानंद राय ने क्षेत्रीय आपदा सहनशीलता और सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में, भारत जोखिम मूल्यांकन, भू-स्थानिक अनुप्रयोगों, प्रभाव-आधारित पूवार्नुमान, पूर्व चेतावनी प्रसार और जलवायु-सहनशील अवसंरचना नियोजन को शामिल करते हुए एक व्यापक क्षमता निर्माण एजेंडा को आगे बढ़ाएगा।

भारत ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपदा और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए एपीडीआईएम और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र ईएससीएपी, एपीडीआईएम और अन्य बहुपक्षीय मंचों के साथ साझेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के 10-सूत्री एजेंडे द्वारा निर्देशित है। यह एजेंडा स्थानीय स्तर पर निवेश, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के बीच नेटवर्क को बढ़ावा देने, जोखिम डेटा को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर देता है।

सत्र का समापन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और नवीन रणनीतियों के कार्यान्वयन हेतु साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ। विचार-विमर्श के दौरान, एपीडीआईएम पर पिछले वर्ष की गतिविधियों, 2026 में की जाने वाली गतिविधियों और 2020-2030 की रणनीतिक कार्य योजना पर गवर्निंग काउंसिल की विशिष्ट चचाओं पर चर्चा हुई। इस बैठक के परिणाम एपीडीआईएम के समग्र कार्य कार्यक्रम का मार्गदर्शन करेंगे और सेंडाई फ्रेमवर्क तथा सतत विकास के 2030 एजेंडे के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भी सहयोग देंगे।

गवर्निंग काउंसिल के दसवें सत्र में बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, कजाकिस्तान, मंगोलिया और तुर्की सहित सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ-साथ ताजिकिस्तान के पर्यवेक्षक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस सत्र में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) के प्रशासन निदेशक श्री स्टीफन कूपर, एपीडीआईएम की निदेशक सुश्री लेटिज़िया रोसानो, एपीडीआईएम के वरिष्ठ समन्वयक श्री मुस्तफा मोहनघेग, और एपीडीआईएम सचिवालय, ईरान और पर्यवेक्षक संगठनों के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत की श्रम संहिताओं की सराहना की; सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास के लिए वैश्विक प्रगति पर प्रकाश डाला

(जीएनएस)।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 21 नवंबर 2025 को चार श्रम संहिताओं को लागू करने की भारत सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। इन सुधारों को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, न्यूनतम वेतन ढांचे को बेहतर बनाने और संस्थागत क्षमता निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हुए इन वैश्विक निकायों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के प्रयास समावेशी और आधुनिक श्रम प्रणालियों पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी टिप्पणियां वैश्विक श्रम और सामाजिक सुरक्षा मानकों को आकार देने में भारतीय नेतृत्व की पहल को दशार्ती है।

आईएलओ महानिदेशक ने भारत के श्रम सुधारों की सराहना की

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के महानिदेशक ने अपनी पोस्ट में कहा: "सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी को शामिल करते हुए आज घोषित भारत की नयी श्रम संहिताओं के घटनाक्रमों पर ध्यान रख रहा हूं। सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सामाजिक संवाद जरूरी रहेगा क्योंकि सुधारों को लागू किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे श्रमिकों और व्यवसायों के लिए सकारात्मक हों।"

आईएसएसए ने भारत की श्रम संहिताओं का स्वागत किया

आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स" पर अपनी पोस्ट में कहा: "भारत की श्रम संहिताएं मजबूत

और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं। आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है और इसके दायरे, सुरक्षा तथा संस्थागत क्षमता में निरंतर निवेश को प्रोत्साहित करता है।"

भारत की श्रम संहिताओं, विशेष रूप से उचित वेतन को बढ़ावा देने, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने और कार्यबल के अधिक औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने के प्रति प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के ये बयान सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को दशार्ते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने तथा सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक संस्थानों और घरेलू हितधारकों के साथ निरंतर सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है।

सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक की मुख्य विशेषताएं

(जीएनएस)।

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (एसएमएफसीएल) ने अपनी वार्षिक आम बैठक में देश के समुद्री वित्तपोषण तंत्र को मजबूत करने के लिए एक दूरदर्शी योजना को मंजूरी दी है। बोर्ड ने 25,000 करोड़ रुपये की कुल उधार सीमा को मंजूरी दी, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एसएमएफसीएल अपने संसाधन जुटाने की योजना के अनुसार अग्रणी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बॉन्ड जारी करने वालों के माध्यम से धन जुटाएगा जिससे निगम शीघ्र ही ऋण देने का कार्य शुरू कर सकेगा।

एसएमएफसीएल वर्तमान में प्रमुख वित्तीय रेटिंग एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श कर रही है। सकारात्मक क्षेत्रीय दृष्टिकोण और एक मजबूत परियोजना पाइपलाइन के साथ निगम को शीर्ष स्तर पर रेटिंग मिलने की उम्मीद है। इससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा और ब्याज लागत को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी। अपनी रणनीतिक योजना के एक भाग के रूप में, एसएमएफसीएल ने संपूर्ण समुद्री मूल्य श्रृंखला को समर्थन देने के लिए एक व्यापक वित्तपोषण ढांचे की रूपरेखा तैयार की है। इसमें बंदरगाहों, बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं, बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण, तटीय सामुदायिक विकास, तटीय नौवहन और अंतदेर्शीय जलमार्गों के लिए वित्तपोषण शामिल है, जिसमें पोत वित्तपोषण पर विशेष जोर दिया गया है।

निगम भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जिससे वैश्विक जहाज निर्माण क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति बनाने की राष्ट्र की महत्वाकांक्षा में योगदान मिलेगा। इस क्षेत्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एसएमएफसीएल पात्र सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को समायोजित ऋण उत्पाद प्रदान करेगा। इसमें अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक वित्तपोषण के साथ-साथ नकदी प्रवाह असंतुलन और गैर-निधि-आधारित प्रक्रियाओं के लिए सहायता भी शामिल होगी।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी)- 2025 में एसआरएफटीआई कोलकाता, एफटीटीआई पुणे और एफटीटीआई ईटानगर के स्टूडेंट्स के लिए मास्टरक्लास सीरीज की शुरूआत

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी)- 2025 में एक विशेष मास्टरक्लास सीरीज की शुरूआत प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के सत्र के साथ हुई।

यह सीरीज कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीटीआई) और एफटीटीआई ईटानगर के स्टूडेंट्स के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य तीनों राष्ट्रीय फिल्म संस्थानों के उभरते फिल्मकारों को एक साथ लाकर सीखने का मंच उपलब्ध कराना है।

सीरीज का पहला सत्र 'द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग' विषय पर काला अकादमी, गोवा के ब्लैक बॉक्स थिएटर में आयोजित किया गया। दंगल, छिछोरे, गैंग्स ऑफ वासेपुर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में अपने योगदान के लिए मशहूर मुकेश छाबड़ा ने कास्टिंग की कला और प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कास्टिंग सिर्फ कलाकार चुनने तक सीमित नहीं है बल्कि यह किरदार की गहरी समझ, असली प्रतिभा की पहचान और ऐसे प्रदर्शन गढ़ने की प्रक्रिया है जो फिल्म के भावनात्मक पक्ष को मजबूत बनाते हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कास्टिंग निर्देशक की दृष्टि और अभिनेता की प्रस्तुति के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम करती है। साथ ही उन्होंने नए कलाकारों को खोजने में अंतर्दृष्टि, अवलोकन कौशल और संवेदनशीलता की महत्ता पर भी प्रकाश डाला।

स्टूडेंट्स ने सत्र में बड़ी सक्रियता दिखाई और इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली, कैरेक्टर ब्रेकडाउन और ऑडिशन प्रक्रिया से जुड़े सवाल पूछे। मुकेश छाबड़ा ने उन्हें ईमानदारी, अनुशासन और जिज्ञासा के साथ सिनेमा से जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने याद दिलाया कि फिल्म में हर भूमिका, चाहे बड़ी हो या छोटी कहानी की संपूर्णता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथ ही उन्होंने कास्टिंग प्रैक्टिस से जुड़े अपने अनुभव साझा किए, जिनमें करियर मार्गदर्शन और उभरते अभिनेताओं व फिल्मकारों के लिए व्यावहारिक सुझाव शामिल थे।

यह सत्र पूरी मास्टरक्लास सीरीज के लिए एक रचनात्मक और प्रेरणादायक शुरूआत साबित हुआ, जो 27 नवंबर 2025 तक चलेगी। आने वाले दिनों में निर्देशकीय कला, पटकथा लेखन, सिनेमैटोग्राफी, साउंड डिजाइन और प्रोडक्शन जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख उद्योग विशेषज्ञ संवादात्मक सत्र में भाग लेंगे, जिनका उद्देश्य स्टूडेंट्स के व्यावसायिक कौशल और रचनात्मक आत्मविश्वास को और मजबूत करना है। यह पहल इफ्फी की उस निरंतर प्रतिबद्धता को दशार्ती है, जिसमें वह नई प्रतिभाओं को संवारने और अगली पीढ़ी के फिल्मकारों के लिए सहयोगात्मक सीख के नए मंच तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।

इफ्फी के बारे में

1952 में स्थापित, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) दक्षिण एशिया के सिनेमा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सिनेमा महोत्सव रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और गोवा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा (ईएसजी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह महोत्सव एक वैश्विक सिनेमाई शक्ति केंद्र बन चुका है-जहां बहाल किए गए क्लासिक्स का संगम साहसिक प्रयोगों से होता है और जहां दिग्गज उस्तादों के साथ नए फिल्मकार भी एक ही मंच साझा करते हैं। जो चीज इफ्फी को खास बनाता है, वह है इसका जीवंत मिश्रण- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रदर्शन, मास्टरक्लास, श्रद्धांजलि, और जोश से लबरेज वेव्स फिल्म बाजार, जहाँ विचार, सौदे और सहयोग उड़ान भरते हैं। गोवा के मनमोहक समुद्री तटों की पृष्ठभूमि में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाला 56वां संस्करण भाषाओं, शैलियों, नवाचारों और आवाजों का एक शानदार संगम पेश करने का वादा करता है जो वैश्विक मंच पर भारत की रचनात्मक प्रतिभा का एक डूबो देने वाला उत्सव है।

मीडिया प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी

प्रयागराज (जीएनएस)।

यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने सभी सहयोगियों के साथ माघ मेला की तैयारियों को देखने, मां गंगा एवं श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन-पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि माघ मेला की तैयारी शुरू हो गयी है। कहा कि 2024 की तुलना में अबकी बार मेले के दायरे को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि माघ मेले का आयोजन 03 जनवरी-पौष पूर्णिमा से प्रारम्भ होकर, मकर संक्रांति-15 जनवरी, मौनी अमावस्या-18 जनवरी, बसन्त पंचमी-23 जनवरी, माघी पूर्णिमा-01 फरवरी एवं महाशिवरात्रि-15 फरवरी, 2026 तक कुल 44 दिनों तक होगा। यहां पर कल्पवासियों की बड़ी संख्या रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरे मेला अवधि के दौरान लगभग 12 से 15 करोड़ लोगो के स्नान करने का अनुमान है। उन्होंने सिंचाई विभाग को मेले में 10 हजार क्यूसिक जल की उपलब्धता बनाये रखने तथा नमांमि गंगे को जल की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। विद्युत विभाग मेले में नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी को बनाये रखने की व्यवस्था करेगा। पीडब्लूडी

कनेक्टिंग मार्गों के साथ-साथ 7 पाण्टुन पुल के निर्माण कराने, चकर्ड प्लेट बिछाये जाने सहित अन्य निर्धारित कार्यों को करेगा, जिससे आवागमन में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार असुविधा न हो। जल निगम के द्वारा मेला क्षेत्र में 242 किमी0 की पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने के साथ 85 किमी0 की सीवर लाइन भी बिछायी जा रही है। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन का एक बूंद भी पानी बिना ट्रीटमेंट के गंगा एवं यमुना जी में न जाये, यह सुनिश्चित किया जाये। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के त्वरित उपचार हेतु 20-20 बेड के दो हॉस्पिटल मेले में बनाये जा रहे है। इसके साथ ही 5-5 आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय के साथ 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था की जायेगी। मेले में नगर विकास के द्वारा 25 हजार शौचालय, 8 हजार डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 30 सक्सन गाड़िया, 3 हजार सफाई कर्मी, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की जायेगी। इस बार मेले को 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 7 सेक्टरों में बसाया जायेगा और 42 स्थानों पर अलग-अलग से रूट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेले को सकुशल रूप से सम्पन्न कराये जाने के लिए यहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक की तैनाती की जा रही है। मेले में नगर विकास के द्वारा सीसीटीवी कैमरा व 400 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरों के माध्यम से क्राउड की निगरानी के साथ स्वच्छता व सुरक्षा की निगरानी भी की जायेगी। माघ मेला में लगभग 3800 बसे लगायी जायेगी, जिसमें परिवहन निगम की लगभग 3000 बसें, 75 शटल बसे मेला क्षेत्र के अंदर लगेगी तथा 200 रिजर्व बसे रहेगी। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेले को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी की जा रही एवं आगामी माघ मेले के आयोजन को पूरी भव्यता, दिव्यता के साथ सम्पन्न कराया जायेगा।

पीलीभीतः बीसलपुर पशु चिकित्सालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला - डॉ. योगेंद्र व अनिल के संरक्षण में रिश्वतखोरी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल!

बीसलपुर। जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर स्थित पशु चिकित्सालय इन दिनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है। स्थानीय पशुपालकों का कहना है कि यहां डॉ. योगेंद्र और अनिल के संरक्षण में रिश्वत का खुला खेल चल रहा है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पर्चा बनवाने और दवाइयां लेने के नाम पर मरीजों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं, जिससे गरीब किसान और पशुपालक बेहद परेशान हैं।

सूत्रों के अनुसार, चिकित्सालय में आने वाले पशुओं के इलाज के लिए निर्धारित प्रक्रिया की बजाय स्टाफ सीधे रिश्वत मांगते हैं। एक पशुपालक ने बताया, दवाइयां भी फ्री की बजाय पैसे लेकर दी जाती हैं।" यह समस्या कई महीनों से चली आ रही है, और पहले भी कई शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंचीं, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

हैरानी की बात तो यह है कि रिश्वत लेते हुए कर्मचारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, फिर भी विभागीय स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टाफ पैसे गिनते हुए पकड़ा गया। पशुपालकों का आरोप है कि लिए गए रिश्वत के पैसे का हिसाब डॉक्टरों को देना पड़ता है, जो पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ को उजागर करता है।

स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विभाग से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

जब डॉक्टर योगेंद्र का बर्जन लेने के लिए फोन पर की गई बात तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है और मुझे नहीं मालूम है कि कौन स्टाफ अस्पताल में बैठा हुआ है वहीं सूत्रों की माने ने तो वहां के लोगों को कहना है कि डॉक्टर अभी यहां से उठ कर गए थे और यह जो लड़का है यह कई महीनो से यही काम करता है

सट्टेबाजी का काला कारोबार फूटा, ढका गांव में प्राइमरी स्कूल के पास कासिम उर्फ छोटू को सट्टा पर्चियां लगाते रंगे हाथों गिरफ्तार

(जीएनएस)।

पीलीभीत जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने की मुहिम के तहत पूरनपुर कोतवाली पुलिस ने एक और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया।कोतवाली पुलिस ने मुखबिर टिप पर छापा मारा, हजारों की सट्टेबाजी का खुलासा, पूछताछ में कबूला अपराध, जेल भेजा, जिले में जुआ माफिया पर पुलिस की सख्ती तेज,ढका गांव के प्राइमरी स्कूल के आसपास सट्टेबाजी का धंधा चला रहे युवक कासिम उर्फ छोटू (पुत्र मल्लू बक्स, निवासी ढका नूरी मस्जिद) को सट्टा पर्चियां बांटते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से सैकड़ों सट्टा पर्चियां व नकदी बरामद हुई। पूछताछ में उसने जुआ कानून का उल्लंघन कबूल किया। एसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी की अगुवाई में टीम ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल रवाना कर दिया। इलाके में सट्टेबाजों में हड़कंप, ग्रामीणों में खुशी का माहौल।

घटना शुक्रवार शाम ढका गांव के प्राइमरी स्कूल के पास घटी। स्थानीय निवासियों की गुप्त शिकायत थी कि स्कूल के बाहर युवक सट्टा पर्चियां बांटकर लोगों को फंसाने का काम कर रहा। मुखबिर की पुष्ट सूचना पर कोतवाली इंस्पेक्टर व हमराही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। संदिग्ध को घेर लिया, तलाशी ली तो उसके पास सट्टे की पर्चियां (जिनमें सैकड़ों नंबर व दांव की डिटेल्स), छोटी राशि की नकदी व मोबाइल फोन बरामद। आरोपी घबरा गया, पूछताछ में नाम-पता बताया व कबूला, "मैं रोज शाम को यहां सट्टा लगाता हूं, आसपास के लोग खेलते हैं।" कोतवाली प्रभारी ने बताया, "ये सट्टेबाजी का छोटा नेटवर्क था, लेकिन स्कूल जैसी संवेदनशील जगह पर धंधा असहनीय। जुआ अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज, मेडिकल व अन्य विधिक कार्रवाई पूरी। आगे अन्य संलिप्तों की तलाश।"

एसपी अभिषेक यादव ने कहा, "जुआ-बोरा जैसे सामाजिक बुराइयों पर जीरो टॉलरेंस। ग्रामीण क्षेत्रों में मुखबिर नेटवर्क मजबूत किया। सट्टेबाजों को चेतावनी - फरार न रहें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई।" क्षेत्राधिकारी ने सराहा, "टीम की फुर्ती से सफलता। इलाके में गश्त व चेकिंग बढ़ाई, स्कूल-मंदिर जैसे स्थानों पर नजर।" ग्रामीणों का कहना, "स्कूल के पास सट्टा? बच्चे प्रभावित हो सकते थे। पुलिस का धन्यवाद, अब सुरक्षित माहौल।" जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से सक्रिय था, संभावित सहयोगी पर नजर। जिले में ऐसी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी, अपराध दर घटी।

गैर इरादतन हत्या के वांछित पिता-पुत्र रामप्रसाद व जितेंद्र गिरफ्तार, आला कत्ल डंडा बरामद

(जीएनएस)।

पीलीभीत जिले के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के दो वांछित अभियुक्तों को आला कत्ल (डंडा) समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया बादशाह की मारपीट से मौत, मुखबिर टिप पर गाजीपुर कुंडा से दबोचे, एसपी निर्देश में उनि श्रीष चंद्र की टीम का एक्शन, कोर्ट भेजे, परिवारिक झगड़े में सनसनी,एसपी के कुशल निर्देशन व सीओ बीसलपुर के नेतृत्व में थाना बरखेड़ा पुलिस ने मुखबिर सूचना पर रामप्रसाद (57 वर्ष, पुत्र बेनीराम) व उसके बेटे जितेंद्र (33 वर्ष, पुत्र रामप्रसाद), दोनों ग्राम पचपेड़ा पुख्ता के निवासी, को गाजीपुर कुंडा तिराहा से पकड़ा। अभियुक्तों की निशानदेही पर डंडा बरामद। मु0अ0सं0 421/2025 धारा 105/351(2)/3(5) इठर में मुकदमा, कोर्ट में पेश। घटना परिवारिक विवाद से जुड़ी, इलाके में दहशत।

घटना 16 नवंबर को पचपेड़ा गांव में घटी। वादी गोकरनलाल (पुत्र बेनीराम) ने बताया, "अभियुक्तों ने मेरे बेटे बादशाह से कहा-सुनी पर लाठी-डंडों से पीटा। बादशाह घायल, बरेली अस्पताल में 18 नवंबर को मौत।" सूचना पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। वांछित आरोपी फरार थे, लेकिन मुखबिर टिप पर छापा। उनि श्रीष चंद्र ने कहा, "टीम ने फुर्ती दिखाई। हथियार बरामद, पूछताछ में कबूला। परिवारिक झगड़ा था, लेकिन हत्या गंभीर।" एसपी ने सराहा - "अपराध पर लगाम, मुखबिरों को प्रोत्साहन।"

गिरफ्तार अभियुक्तः

1. रामप्रसाद पुत्र बेनीराम, ग्राम पचपेड़ा पुख्ता, बरखेड़ा।
2. जितेंद्र पुत्र रामप्रसाद, ग्राम पचपेड़ा पुख्ता, बरखेड़ा।

गिरफ्तारी टीमः

1. उनि श्री श्रीष चंद्र।
2. हे.का. मो. अली।
3. हे.का. भुल्लन सिंह।

ग्रामीणों ने राहत - "परिवारिक दुश्मनी खत्म, न्याय मिला।" जांच जारी, अन्य संलिप्तों पर नजर।

ब्रेन हैमरेज के चलते शिक्षामित्र की हुई इलाज के दौरान ह मौत

(जीएनएस)।

मलिहाबाद।

मलिहाबाद के सराँवा गाँव मे प्राथमिक विद्यालय सराँवा मे तैनात शिक्षामित्र विजय कुमार वर्मा (50) की शुक्रवार को एक निजी अस्पताल मे ईलाज के दौरान मौत हो गई। डाक्टरों ने ब्रेन हैमरेज के चलते मौत होने की पुष्टि की है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि एसआईआर ड्यूटी के दौरान जिम्मेदारों के फोन व वर्कलोड से हुआ ब्रेन हैमरेज।

मलिहाबाद के सराँवा गांव निवासी विजय कुमार वर्मा गाँव के ही प्राथमिक विद्यालय मे शिक्षामित्र थे। पत्नी संगीता रावत ने बताया कि विजय एसआईआर मे बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे। तहसील के जिम्मेदार लोगों द्वारा विजय को बार बार फोन किया जा रहा था। वह दिनरात बीएलओ का काम कर रहे। आरोप है कि काम का अत्यधिक दबाव और बार बार फोन आने से विजय काफी परेशान थे।

संगीता ने बताया कि इसी दबाव के चलते 14 नवम्बर को विजय को ब्रेन हैमरेज व पैरालाईसिस अटैक पड गया। उन्हे चरक अस्पताल लखनऊ मे भर्ती कराया गया। 15 नवम्बर को बीएलओ और अधिकारियो के ग्रुप पर इसकी लिखित सूचना दिये जाने के साथ ही ईलाज के लिये आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई गयी। मगर अभीतक किसी भी जिम्मेदार का कोई सहयोग नही मिला। मृतक परिवार मे पत्नी संगीता रावत और बेटा हर्षित वर्मा है।शिक्षामित्र विजय गुप्ता का कहना है कि दबाव के चलते पूरा दिन काम करते थे रात-रात काम करते थे काम में दबाव बहुत है इस काम को सही तरीके से करना चाहिए सर हम लोगों को सुविधा दी जाए दबाव बनाकर कार्य नहीं करना चाहिए। इसी दबाव के चलते आज अपने साथी को खो दिया ब्रेन हेमरेज के चलते उनकी मृत्यु हो गई।

मंडी में धान खरीद को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन उपजिलाधिकारी को सौंपा चार-सूत्री ज्ञापन!

(जीएनएस)।

बीसलपुर/पीलीभीत। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की ओर से स्थानीय किसानों ने अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी बीसलपुर को एक प्रार्थना-पत्र सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में धान की खरीद में अनियमितताएँ हो रही हैं तथा सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों का सही ढंग से पंजीकरण और तौल नहीं की जा रही है।

किसानों ने प्रार्थना-पत्र में बताया कि वह कई दिनों से धान बेचने के लिए मंडी और क्रय केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो तौल स्लिप मिल रही है और न ही ऑनलाइन पंजीकरण में सुधार किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण

उनकी फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है।

किसानों ने यह भी बताया कि यूपीएसएस पोर्टल पर गड़बड़ियों के कारण कई किसानों का नाम सूची में दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे खरीद प्रक्रिया बाधित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र प्रभारी और संबंधित कर्मचारियों द्वारा शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने मांग की है कि—

1. सभी किसानों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से सही कराया जाए।
2. क्रय केंद्रों पर पारदर्शी ढंग से तौल और खरीद सुनिश्चित की जाए।
3. जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
4. किसानों की फसल खराब होने से बचाने के लिए तुरंत राहत कदम उठाए जाएँ।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से आग्रह किया कि किसान हितों को ध्यान में रखते हुए त्वरित कदम उठाए जाएँ।

पीलीभीतः सपा नेत्री दिव्या गंगवार व समाजसेवी चौ. प्रदीप पटेल ने मुलायम सिंह की जयंती माला पहनकर मनाई, विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प!

बीसलपुर विधानसभा कार्यालय पर कार्यक्रम; सालिक राम गंगवार, रूपलाल महातिया सहित कई नेता उपस्थित

(जीएनएस)।

बीसलपुर/पीलीभीत।जनपद की विधानसभा 130 बीसलपुर में समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी दिव्या पी. गंगवार के आवास/कार्यालय पर आज श्रद्धेय नेताजी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नेताजी के संघर्षों, सिद्धांतों एवं समाजवादी विचारधारा को याद करते हुए उपस्थित नेताओं ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में सपा महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती दिव्या गंगवार ने कहा कि नेताजी की नीतियाँ आज भी समाज को सही दिशा प्रदान करती हैं। उन्होंने कार्यकताओं से आवाहन किया कि वे संगठन को मजबूत करने एवं समाजवादी मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

इस अवसर पर चौधरी प्रदीप पटेल, सालिक राम गंगवार, रूपलाल महातिया, रवि गंगवार, राजेश कुमार,

पंकज कुमार, अवी गंगवार, भूदेव गंगवार, फैजान खान, सलीम रजा सहित कई सम्मानित नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पीलीभीतः बरखेड़ा में लेखपाल ने बिना जांच के फाइनल रिपोर्ट लगाई, हरिशंकर शर्मा ने जिलाधिकारी को शिकायत- अमित गुप्ता ने रास्ता रोका!

- निजी रास्ते पर पैकड़िया व गंदा पानी मोड़ने का आरोप; तहसील में दबा मामला, ईओ प्रभार एसडीएम के पास- कार्रवाई की मांग

पीलीभीत (जीएनएस)।

बरखेड़ा नगर में लेखपाल द्वारा बिना जांच किए फाइनल रिपोर्ट लगाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। हरिशंकर शर्मा पुत्र ब्रह्मदत्त शर्मा, निवासी बरखेड़ा तथा स्थानीय पत्रकार ने इस संबंध में जिलाधिकारी पीलीभीत को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस के अनुसार लगभग एक माह पूर्व उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया था कि उनके पूर्वजों के निजी रास्ते पर अमित गुप्ता पुत्र कमलेश गुप्ता द्वारा दबंगई के बल पर जबरन पक्का निर्माण (पैकड़िया) कर दिया गया है तथा रास्ते की ओर लैट्रिन, बाथरूम एवं गुसलखाने का पानी प्रार्थी की तरफ मोड़ दिया गया है।

शिकायत मिलने के बावजूद मामला लंबे समय तक तहसील बीसलपुर में दबा रहा। इसके बाद में जन सुविधा केंद्र पर आवेदन की

स्थिति निकलवाई, जिसमें यह पाया गया कि संबंधित लेखपाल ने बिना किसी स्थल निरीक्षण के रिपोर्ट लगाकर प्रकरण को निस्तारित कर दिया है।

रिपोर्ट में लेखपाल ने उल्लेख किया था कि "दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई पक्ष नहीं माना", जबकि कहना है कि लेखपाल ने न तो उनसे संपर्क किया और न ही मौके पर कोई जांच की। आरोप लगाया है कि लेखपाल ने कथित रूप से अमित गुप्ता से मिलीभगत कर रिपोर्ट लगा दी है।

हरिशंकर शर्मा ने इस अनियमितता के विरुद्ध पुनः जिलाधिकारी पीलीभीत को तहरीर देकर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि अमित गुप्ता का मूल दरवाजा उत्तर दिशा की ओर था, लेकिन अब दबंगई के तहत की ओर पाइप व कड़िया निकालकर रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है।

इधर नगर पंचायत बरखेड़ा का अधिशासी अधिकारी (ईओ) का अतिरिक्त प्रभार एसडीएम बीसलपुर के पास है, जिससे नगर के कई मामलों में कार्रवाई लंबित पड़ी हुई है। स्थानीय लोग अब यह देखने को मजबूर हैं कि जिलाधिकारी महोदय तथा अधिशासी अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और लेखपाल द्वारा बिना जांच की गई रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जाती है।

भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा चीन, हिंद महासागर में तनाव! इन तीन हरकतों से उकसा रहा ड्रैगन

वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति दिखाने की चीन की नीति का एक अहम हिस्सा हिंद-प्रशांत क्षेत्र (क्ल्लङ्क्ष-ढ्ढ्रू र्फ्रेङ्कल्ल) में उसका तेजी से बढ़ता प्रभाव है। हालांकि बीजिंग ने हिंद-प्रशांत की कोई औपचारिक या स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, लेकिन इस क्षेत्र में उसकी बढ़ती गतिविधियां रणनीतिक संतुलन को बदलने और बिगाड़ने में लगी हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्व और चीन की भूमिका

हिंद-प्रशांत, जो हिंद और प्रशांत महासागरों से मिलकर बना एक विशाल क्षेत्र है, आज चीन की रणनीति का प्रमुख केंद्र बन चुका है। प्रशांत क्षेत्र में चीन फिलीपींस और जापान जैसे देशों के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय संघर्षों में लगातार उलझा है।

दक्षिण चीन सागर में बढ़ते समुद्री तनाव

दक्षिण चीन सागर (रउर) में चीन की आक्रामक गतिविधियों के कारण चीनी तटरक्षक और समुद्री मिलिशिया तथा फिलीपींस के तटरक्षक के बीच कई शारीरिक टकराव हो चुके हैं। जिस पर भारत से लेकर अमेरिका तक ने ऐतराज जताया है।

हिंद महासागर में चीन की अलग रणनीति

हिंद-प्रशांत के दूसरे हिस्से-हिंद महासागर-में चीन की रणनीति प्रशांत क्षेत्र से अलग है। यहां चीन भले ही रणनीतिक उथल-पुथल का सामना करता हो, लेकिन उसके दीर्घकालिक लक्ष्य लगातार विस्तृत होते जा रहे हैं।

हिंद महासागर में चीन की 3 रणनीतियां

चीन हिंद महासागर में तीन चरणों पर आधारित रणनीति चला रहा हैः

1. तटीय देशों में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना
2. दोहरे-उपयोग वाले शोध पोत भेजकर नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाना
3. चीन-हिंद महासागर फोरम के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना

चीन की 'रणनीतिक प्रयोगशाला'

हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सक्रियता अक्सर अनदेखी रह जाती है, जबकि यह क्षेत्र अब उसके लिए रणनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है, जहां वह नए तरीकों से प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है।

हिंद महासागर और चीन

हिंद महासागर में चीन का इतिहास दो दौर में देखा जाता है-पहले दौर में समुद्री व्यापार और प्रवासन थे, जबकि आधुनिक दौर में सुरक्षा कारणों से उपस्थिति बढ़ी। 21वीं सदी में सोमालिया के पास बढ़ती समुद्री डकैती के बाद चीन ने दो युद्धपोत भेजकर अपनी सुरक्षा उपस्थिति शुरू की।

चीन की हिंद महासागर में उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। घरेलू और बाहरी दोनों कारक इसके पीछे हैं। मध्य पूर्व से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इसका लगभग 80% तेल आयात हिंद महासागर से होकर गुजरता है। हिंद महासागर चीन के लिए वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है, जहां से वह अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है।

कूटनीति का बुनियादी ढांचा

चीन ने हिंद महासागर में अपने रणनीतिक ङ्क्षङ्क३स्र१ल्ल३ को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर बंदरगाह, हाईवे और एयरपोर्ट बनाए हैं। जिनमें प्रमुख हैं-

पाकिस्तान में ग्वादर

श्रीलंका में हंबनटोटा

बांग्लादेश में सोनादिया

म्यांमार में क्याउकप्यू

कर्ज-जाल कूटनीति का खतरा

ये परियोजनाएं अक्सर उन देशों को भारी कर्ज में डाल देती हैं। यदि वे चूक जाते हैं, तो चीन इन परिसंपत्तियों का परिचालन नियंत्रण मांग सकता है। श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

हिंद महासागर में हाइड्रोग्राफिक अध्ययन के नाम पर चीन कई शोध पोत भेज रहा है-जिनमें उसका सबसे बड़ा महासागरीय पोत ङ्क्षल्लॅ रैंल्ल ऊँ४ भी शामिल है। ये पोत श्रीलंका और मालदीव के तट पर भी रुकते हैं, जिससे भारत चिंतित है। उनकी दोहरी-उपयोग तकनीक खुफिया संग्रहण में मदद करती है।

चीन-हिंद महासागर फोरम, जिसे उकऊउअ द्वारा संचालित किया जाता है, बीजिंग का एक नया प्रयास है जिसे क्षेत्रीय विकास, ब्लू इकॉनमी, समुद्री कनेक्टिविटी और पर्यावरण मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के रूप में पेश किया गया है।